THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) 111 Kendriya Vidyalayas are functioning in U.P. at present.

(b) and (c) Kendriya Vidyalayas are not opened on the basis of the population of a State. These Vidyalayas are primarily for the children of transferably Central Government employees including defence and para-military personnel. Specific locations where new schools are to be opened in 93-94 have not been decided.

(d) Out of 63 districts in U.P. 44 districts are covered by one Navodaya Vidyalaya in each district. The Navodaya Vidyalaya Samiti is keen to open one Vidyalaya in each district as soon as requisite facilities are made available by the State Government and financial resources are provided.

Agitation by Karnataka Raitha Sangha

*260. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the agitation by the Karnataka Raitha Sangha against Government's plan to allow multinational companies in seed production;

(b) whether a US multi-national company was attacked at Bangalore; and

(c) what are the steps taken to prevent the multi-national companies from exploiting Indian agriculturists in seed production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY RESOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR). (a) and (b) Yes, Sir.

(c) MRTP/FERA companies have been permitted to enter the area of certified high yielding seeds from 1986. In the New Policy on Seed Development, 1988 provisions have been made for adequate trials, import of technology/parental seeds, restriction on bulk import on recurrent basis for coarse cereals, pulses, oilseeds and fodder seeds. Bulk import of wheat and paddy seeds was not considered in the Policy. Sale of certified seed is compulsory for MRTP/FERA companies.

उर्वरकों की खपत में कमी

@2126. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि सरकार का ध्यान उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि के कारण उनकी खपत में कमी आने संबंधी समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1993 तक पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में उर्वरकों की बिक्री में आई गिरावट का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन उर्वरकों का ब्यौरा क्या है जिनकी बिक्री कम हुई है और यह कमी कितने प्रतिशत है ;

(घ) क्या उर्वरकों की कम खपत को देखते हुए खाद्यान्नों का उत्पादन कम होने की संभावना है ;

(ङ) क्या सरकार देश के सीमांत और छोटे किसानों को रियायती मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने का विचार रखती है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेतम) : (क) से (ग) निम्नलिखित तालिका उन प्रमुख उर्वरकों की बिक्री को दर्शाती है, जिन्होंने पिछले वर्ष 1 अप्रैल, 1992 से 1 जनवरी, 1993 तक की अनुवर्ती अवधि में हुई बिक्री की तुलना में कमी दर्ज की है :—

	1 अप्रैल, 91 से 31 जनवरी 1,992 तक हुई बिक्री	1 अप्रैल, 92 से 31 जनवरी, 1993 तक हुई बिक्री	प्रतिशत कमी
		(लाख मीटर टन में)	
डी. ए. पी. . .	41.43	34.55	(–) 16.6
एम. ओ. पी. . .	16.94	10.45	(–) 38.3

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 1233, 4 मार्च, 1993 से स्थानान्तरित ।

(घ) फसल उत्पादन पर तत्काल प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है। आशा है कि चालू रबी मौसम के दौरान खाद्य उत्पादन संतोषजनक होगा ।

(ङ) और (च) भारत सरकार ने रबी 1992–93 के दौरान, छोटे और सीमान्त किसानों सहित सभी किसानों को डी.ए.पी., एम.ओ.पी. और उनके योगों की रियायती बिक्री के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 340 करोड़ रुपए निर्मुक्त करने के प्रावधान की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, छोटे और सीमान्त किसानों को लाभ हेतु 500 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, ताकि उन्हें अवसंरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकें।

Funds for Horticulture Development in Arunachal Pradesh

2127. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what was the total amount of fund earmarked for Horticulture Development in Arunachal Pradesh during 1989-90, 1990-91 and 1992;

(b) how many hectares of horticulture gardens are exising in the State, district-wise;

(c) whether the productions of these gardens are sufficient to feed only the State's food processing unit at NINGMAI, West Siang district; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) The details of the funds earmarked for horticulture development in Arunachal Pradesh during 1989-90, 1990-91 and 1991-92 under Central and State-sectors are as under:—

Year	Central Sector	State Sector
	(Rs in lakhs)	
1989-90	0.095	126.45
1990-91 . .	5.48	200.45
1991-92 .	11.53	302.00